साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 7, अंक : 44 (प्रति बुधवार), इन्दौर 22 जून 2022 से 28 जून 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल योग कार्यक्रम में हुए शामिल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में हुआ सामूहिक योग

भोपाल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में हुए योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मैसूर पैलेस में दिए गए उद्बोधन और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का लाइव प्रसारण देखा।

राज्यपाल श्री पटेल ने सामूहिक रूप से आसन, प्राणायाम और ध्यान की यौगिक क्रियाओं में भाग लिया। राज्यपाल के साथ करीब 200 व्यक्ति ने सामूहिक रूप से ग्रीवा चालन, स्कंध संचालन, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, कटिचक्रासन, दण्डासन, वज्रासन, तितली आसन, उष्ट्रासन, शशांकासन, उत्तानमंडूकासन, वक्रासन, मकरासन, सेतुबंध आसन, उत्तानपादासन, पवनमुक्तासन और शवासन किए। आसनों के बाद कपालभाति, नाड़ीशोधन, अनुलोम-विलोम, शीतली, उज्जायी, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम किए। ध्यान, क्लेपिंग एवं लाफिंग थेरेपी के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम को विराम दिया गया। संचालन योग गुरु श्री राजीव जैन त्रिलोक ने किया। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री डी.पी. आहूजा सहित राजभवन के अधिकारी, कर्मचारी, परिजन और प्राथमिक माध्यमिक शाला कुम्हारपुरा के स्कूली बच्चे और शिक्षक भी शामिल हुए।

नागरिक सुविधा के लिए एक प्रकृति के पोर्टल्स को किया जाए समन्वित

भोपाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए भिन्न-भिन्न पोर्टल का उपयोग करना पड़ता है। सभी पोर्टल की अलग-अलग जटिलताएँ हैं। इससे नागरिकों की समस्याएँ बढ़ती हैं। विभाग पोर्टल्स की संख्या कम करने की दिशा में कार्य करें। नागरिक सुविधा को देखते हुए एक प्रकृति के पोर्टल को समन्वित किया जाए। विभिन्न सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल बनाने की दिशा में समय-सीमा निर्धारित कर कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में सिटीजन सर्विस डिलिवरी पोर्टल संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री अमित राठौर, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड श्री नंद कुमारम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बताया गया कि सिटीजन सर्विस डिलिवरी के लिए हितग्राही मूलक प्रमाण-पत्र प्रदान करने संबंधी सेवा को ई-सर्विस पोर्टल अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लाया जाएगा। एक सेक्टर के विभागों की सिटीजन आधारित योजनाओं के लिए एक समान गतिविधियों से संबंधित विभागों जैसे कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता आदि के लिए एक प्रकार का पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार हितग्राही को भुगतान संबंधी योजनाओं के लिए एक पोर्टल तथा सब्सिडी के लिए भी एक ही पोर्टल बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

योग बेहतर जीवन जीने की एक कला है -मंत्री डॉ. मिश्रा

भोपाल जेल एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में सेंट्रल जेल में बंदियों के साथ योग किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मंत्री डॉ. मिश्रा ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि योग बेहतर जीवन जीने की कला है।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल के सांस्कृतिक भवन में जेल महानिदेशक श्री अरविंद कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी श्री अशोक अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एसपीएस बुंदेला, डीआईजी जेल श्री संजय पांडे और श्री एम.आर. पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद दुबे, जेल अधीक्षक श्री दिनेश नरगावे और लगभग 150 बंदियों के साथ योग किया। सेंट्रल जेल भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लगभग 4000 कैदियों ने अलग-अलग स्थानों पर योग किया। मंत्री डॉ. मिश्रा के साथ सभी उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रसारित संदेश को ऑन-स्क्रीन सुना। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आह्वान पर हमें योग को वृहद स्तर पर प्रसारित करना है। उन्होंने कहा कि योग अब हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं है अपितु जीवन जीने का एक तरीका बन गया है। योग हमें सिर्फ निरोग ही नहीं रखता है, बल्कि बेहतर जीवन जीने की कला को भी सिखाता है।

सादगी से मनाया योग दिवस

ओबेदुल्लागंज। ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने विश्व धरोहर भीम भीम बेटिका में 8 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। जिसमे स्कूल के 25 बच्चों एवं शिक्षकों ने योग विशेषज्ञ जीतू यादव के नेतृत्व में योगा किया। प्राणायाम से लेकर योगाभ्यास तक, योग के विस्तृत आसन बच्चों नें शिक्षकों के साथ किये है। इस अवसर पर बच्चों को योग से लाभ और निरोग रहने के आसन सिखाए गए। साथ ही योग दिवस की महत्वता और हमारी जीवन शैली में योग की निरंतरता का उद्देश्य बच्चों को समझाया गया। प्राचार्या ने बच्चों को बताया कि हम नियमित रुप से योगासन के अभ्यास की आदत बनाकर शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ और फिट बने रह सकते है इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर प्रांगण में भी योग दिवस विशेष आयोजन संपन्न हुए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भोपाल गैस पीड़ित दूषित पानी पीने पर मजबूर

भोपाल। बीसवीं सदी की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना का असर भोपाल पर पिछले 38 सालों से बना हुआ है। और यह नहीं मालूम कि आगे कब तक बना रहेगा। लेकिन इसके असर से बचने के लिए बनाई गई सुरक्षा की दीवारों को आए दिन सरकारी महकमा तो तोड़ता ही है, साथ ही यह महकमा ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि इससे पीड़ित स्वयं भी इसमें शामिल हो जाते हैं।

भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास बसी 42 बस्तियों में, जहां अदालती आदेश के बावजूद पीने का स्वच्छ जल नसीब नहीं हो पा रहा है और वे उस भूजल को पीने को मजबूर है, जिसके उपयोग पर अदालत ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ की रिपोर्ट के आधार पर उपयोग पर रोक लगा रखी है। पीड़ित संगठनों द्वारा यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की वजह से इसके आसपास की बस्तियों में लगातार फैल रहे भूजल प्रदूषण और साफ पानी मुहैया कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति को पत्र लिखा है। पत्र में समिति के चेयरमैन जस्टिस शील नागु और सदस्य सचिव राजीव कारमाहे से जल्द बैठक बुलाने और निरीक्षण करने के लिए आग्रह किया गया है। ध्यान रहे कि यूनियन कार्बाइड की दुर्घटना के बाद यहां के भूजल में घातक रसायन बड़ी मात्रा में जमीन के नीचे चले गए हैं और लगातार समय बीतने के साथ और भी यहां के भूजल को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे में यहां का पानी किसी जहर से कम नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने यहां पेयजल की आपूर्ति के लिए अपने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास की 42 बस्तियों के भूजल को पेयजल के रूप में उपयोग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नौ साल पहले ही रोक लगा दी थी। आदेश दिया था कि इन बस्तियों के लिए राज्य सरकार बकायदा पाइप लाइन बिछा कर स्वच्छ जल मुहैय्या कराए। यही नहीं आदेश में यह भी कहा गया कि अदालत द्वारा बनाई निगरानी कमेटी हर चार माह में इस पाइप लाइन से सप्लाई होने वाले पानी की जांच कर इसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट देगी। लेकिन निगरानी कमेटी मार्च, 2019 से अब तक कभी जांच नहीं की। पिछले एक हफ्ते से पाइप लाइन से आने वाला पानी की आपूर्ति भी अनियमित हो गई है। यह पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पिछले डेढ़ सालों में कई बार हो चुका है। ऐसे हालात में बस्तिवासी यहां ट्यूब वेल का पानी पीने पर मजबूर हैं। भोपाल ग्रुप फॉर इंफोर्मेशन एंड एक्शन की अध्यक्ष रचना ढींगरा ने बताया कि 2021 में तो यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास के इंद्रा नगर में लोक यांत्रिकी विभाग द्वारा विधायक निधि से एक बोरवेल तक खुदवाया जा रहा था, यह जानते हुए भी कि इस बस्ती का भूजल यूनियन कार्बाइड कारखाने के जहरीले कचरे के कारण प्रदूषित है और अदालती रोक है। भूजल प्रदूषण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले में पहले से ही आदेश है कि इन क्षेत्रों में पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए और सारे सरकारी बोरवेल को सील कर बंद किए जाने के आदेश हैं ताकि स्थानीय रहवासी प्रदूषित भूजल का सेवन ना करें। इसके बावजूद क्षेत्र में विभाग की तरफ से बोरवेल का खनन किया जा रहा था जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का खुला उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि विभागों को यूनियन कार्बाइड कारखाना के जहरीले कचरे से आसपास की बस्तियों में फैल रहे जल प्रदूषण पर गंभीर होना चाहिए जो कि नहीं हैं। उनका कहना था कि यदि हम बोर खनन की जानकारी और सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के बारे में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को न बताते तो विभाग और अधिकारी क्षेत्र में बोरवेल का खनन कर चुके होते। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के विधायक तक सात-आठ माह पूर्व लोगों के घरों में हैंडपंप लगवा रहे थे। यही नहीं उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम ने कई सरकारी ट्यूब वेल इलाके के बंद ही नहीं किए हैं अब तक। इलाके में पाइप लाइन से अनियमित पेयजल की सप्लाई होने के कारण लोग चोरीछुपे अपने-अपने घरों में हैंडपंप लगवा रहे है और इस काम में सरकारी महकमा भी मदद कर रहा है। भोपाल इफरमेशन एक्शन की अध्यक्ष रंजना धींगरा ने तो यहां तक बताया कि इस इलाके में स्थानीय विधायकों ने भी हैंडपंप लगवाने में मदद की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां ग्राउंट वाटर से पानी की आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद यहां बस्तियों में नर्मदा का पानी पाइप लाइन के माध्यम से आ रहा था, लेकिन नर्मदा का पानी नगर निगम ने डेढ़ साल पहले बंद कर दिया था और इसकी जगह कोलार बांध और बड़े तालाब का पानी सप्लाई किया जाने लगा। यह पानी भी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है। लेकिन अब तो इस पानी को भी निगम सप्लाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। गैस पीड़ित संगठनों ने बताया कि घातक रसायनों का असर 29 अन्य बस्तियों तक जा चुका है। रचना ढींगरा ने डाउन टू अर्थ को बताया कि यहां संभावना ट्रस्ट ने अब तक पानी की जांच में पाया है कि 42 बस्तियों में भूजल पेयजल के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही उन्होंने लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टॉक्सीकॉलिजिकल रिसर्च सेंटर से आग्रह किया है कि वह यहां आकर एक बार फिर से इस पानी की जांच करें।

साभार - डाउन टू अर्थ

बढ़ते पर्यटन के चलते हिमालयी इकोसिस्टम पर बढ़ रहा है दबाव

शिमला। हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन के चलते हिल स्टेशनों पर दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही पर्यटन के लिए जिस तरह से इस क्षेत्र में भूमि उपयोग में बदलाव आ रहा है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जंगलों का बढ़ता विनाश भी इस क्षेत्र के इकोसिस्टम पर व्यापक असर डाल रहा है।

यह जानकारी हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीएनआईएचई) द्वारा जारी रिपोर्ट एनवायर्नमेंटल एस्सेसमेन्ट ऑफ टूरिज्म इन द इंडियन हिमालयन रीजन में सामने आई है। इस रिपोर्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) को सौंपा गया है। यह रिपोर्ट हिन्दू अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के सन्दर्भ में प्रकाशित की गई है जिसमें कहा गया था कि पर्यटन ने हिमालय क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि तो लाई है लेकिन इसका खामियाजा पर्यावरण को भुगतना पड़ रहा है। देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके भीतर पर्यटन का प्रबंधन अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक समस्या है। उदाहरण के लिए लद्दाख को ही देख लीजिए, जो पहले ही जल संकट की समस्या से ग्रस्त क्षेत्र है। वहां पर्यटन ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र अपनी पानी की मांग के लिए ज्यादातर बर्फ या हिमनदों के पिघलने और सिंधु नदी के प्रवाह पर निर्भर है। इस क्षेत्र में जहां एक स्थानीय निवासी प्रति दिन 75 लीटर पानी का उपयोग करता है वहीं एक पर्यटक के लिए हर रोज करीब 100 लीटर पानी की जरुरत है ऐसे में यह बढ़ी हुई मांग वहां जल स्रोतों पर कहीं ज्यादा दबाव डाल रही है। 16 जून 2022 को एनजीटी की साइट पर डाली गई इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि लद्दाख में संरक्षित क्षेत्रों जैसे हेमिस नेशनल पार्क, चांगथांग कोल्ड डेजर्ट सैंक्चुअरी और काराकोरम सैंक्चुअरी में सतर्कता और नियमित गश्त की जरुरत है, जिससे इस क्षेत्र में वन्यजीव और पर्यटकों के बीच संघर्ष की घटनाओं को टाला जा सके। इतना ही नहीं इस क्षेत्र में ऑफ-रोड ड्राइविंग के कारण इस क्षेत्र में वन्यजीवों का आवास नष्ट हो रहा है और जैवविविधता पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही बढ़ता अतिक्रमण भी नई समस्याएं पैदा कर रहा है। इसी तरह मनाली, हिमाचल प्रदेश में किए एक अध्ययन से पता चला है कि 1989 में वहां जो 4.7 फीसदी निर्मित क्षेत्र था वो 2012 में बढ़कर 15.7 फीसदी हो गया है। इसी तरह 1980 से 2011 के बीच वहां पर्यटकों की संख्या में 1900 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।गौरतलब है कि जहां 1989 में वहां आए पर्यटकों का आंकड़ा 1.4 लाख था वो 2012 में बढ़कर 28 लाख पर पहुंच गया था। जिसका सीधा असर इस क्षेत्र के इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान मौजूदा होटलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसका खामियाजा इस क्षेत्र में हरियाली और जैवविविधता को भुगतना पड़ रहा है। बढ़ते दबाव को कम करने के लिए क्या कुछ किए जा सकते हैं प्रयास

लद्दाख की तरह ही कश्मीर क्षेत्र में भी पर्यटकों की आवाजाही, वायु गुणवत्ता और ठोस कचरे के प्रबंधन पर ध्यान देने की जरुरत है। इसके साथ ही जम्मू में अमरनाथ और माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद सुविधाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल एजेंडा के साथ पर्यटन सम्बन्धी नियमों को दुरुस्त करने की जरुरत है। इसे भारतीय हिमालय क्षेत्र के हर एक पर्यटन स्थल पर कितने पर्यटकों के लिए सुविधाएं मौजूद है और वहां मौजूद बुनियादी ढांचे की कितनी क्षमता है इस सबको ध्यान में रखकर नियंत्रित किया जा सकता है।रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रूप से ठोस कचरे के उत्पादन और प्रदूषण के स्तर को कम करके जल, वायु और जैवविविधता को होते नुकसान को कम किया जा सकता है। ऐसे में रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जहां इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के स्थाई रोजगार को ध्यान में रखना जरुरी है। वहीं साथ ही अनियमित पर्यटन के चलते इस क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को होते नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।रिपोर्ट के मुताबिक उन पर्यटक स्थलों से सबक सीखने की जरुरत है जो पहले ही बढ़ते पर्यटकों का दबाव झेल रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण की मिसाल- खेजड़ी के 1 पेड़ को बचाने के लिये यह ट्रस्ट खर्च रहा है 15 लाख रुपये

बाड़मेर. राजस्थान में एक कहावत है कि 'सिर साटे रूख रहे तो सस्तो जान' यानी सिर के बदले अगर एक पेड़ बचता है तो यह सौदा महंगा नहीं बल्कि सस्ता है. राजस्थान के कई इलाकों में विभिन्न विकास योजनाओं और सोलर एनर्जी के नाम पर बड़ी संख्या में राज्य वृक्ष खेजड़ी के साथ अन्य पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है. इनमें कई जगह तो राजस्थान के कल्प वृक्ष माने जाने वाली खेजड़ी को जड़ों सहित नेस्तनाबूद किया है. लेकिन इन सबके बीच पर्यावरण संरक्षण का एक ऐसा अनूठा उदाहरण सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा. बाड़मेर के श्री मातारानी भटियाणीजी चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से खेजड़ी के एक पेड़ को बचाने के लिये 15 लाख रुपये अतिरिक्त खर्चा आयेगा. दरअसल पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर शहर के जूना केराड़ मार्ग पर इन दिनों श्री मातारानी भटियाणीजी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भव्य श्री माजीसा धाम का निर्माण करवाया जा रहा है. इसमें 60 बाई 80 फीट के भूखंड के बीच में राज्य वृक्ष खेजड़ी का एक पेड़ आ रहा है. संस्थान उसे वहां से हटाने की बजाय येन-केन बचाने का सराहनीय प्रयास कर रहा है. ट्रस्ट की ओर से खेजड़ी को बचाने के लिए मंदिर के नक्शे में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है. इसके साथ ही ट्रस्ट पर इसके लिए करीब 15 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ा है. खेजड़ी के पेड़ को बचाने के साथ ही उसकी गहराई में फाउंडेशन भरके उसे मजबूत भी किया जा रहा है. एक दर्जन से अधिक मजदूर पिछले तीन दिन से यहां जुटे नजर आ रहे हैं. मंगलवार को इस दृश्य को जिसने भी देखा तो वह हृदय से अभिभूत नजर आया. इसके साथ ही लोगों ने ट्रस्ट के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की. ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वरूपचंद और पदाधिकारी सुरेश कुमार तेजमालता बताते हैं कि कुदरत को सहेजने के लिए हर एक पेड़ की जरूरत है और वही ट्रस्ट ने किया है. पेड़ को बचाने के लिए जी जान से जुटे है दर्जनों लोग बाड़मेर में दर्जनों लोग खेजड़ी के एक पेड़ को बचाने के लिए जी जान से जुटे नजर आए. इसके गवाह बन रहे लोगों को कहना कि जब एक संस्थान इस तरह के प्रयास करके पेड़ को बचा रहा है तो सरकारें और निजी कंपनियां पेड़-पौधों को क्यों नहीं बचा सकती है ? वे क्यों लगातार अंधाधुंध उन्हें काटने में लगे हुये हैं. उन्हें बाड़मेर के मातारानी भटियाणी मंदिर निर्माण ट्रस्ट से सीख लेनी चाहिये.

एयर क्वालिटी ट्रैकर- शिलांग-सिलीगुड़ी सहित देश के 35 शहरों में वायु गुणवत्ता रही बेहतर, 50 से कम रहा सूचकांक

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 22 जून 2022 को शाम चार बजे जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 148 शहरों में पाली की हवा सबसे ज्यादा खराब थी, जहां सूचकांक 212 दर्ज किया गया था, जोकि वायु गुणवत्ता के %खराब% स्तर को दर्शाता है। यदि दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो बड़े दिनों बाद एक बार फिर यहां की वायु गुणवत्ता %मध्यम% श्रेणी में आ गई है, जहां सूचकांक 139 दर्ज किया गया है। जबकि देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के %बेहतर% स्तर को दर्शाता है। जबकि कोलकाता में यह इंडेक्स 51, चेन्नई में 59, बैंगलोर में 46, हैदराबाद में 53, अहमदाबाद में 87 और पुणे में 78 दर्ज किया गया।

पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटना भारतीय संस्कृति में निहित-डा.अरुण

फिरोजाबाद। प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण एवं जंतु उद्यान जलवायु मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योग से मनुष्य में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। इसीलिए सभी धर्मों में योग को जीवन का अंग बताया गया है। वह जसराना के एलआर डिग्री कालेज में आयोजित योग कार्यक्रम को मुख्य अतिथि बतौर संबोधित कर रहे थे।

पर्यावरण संबंधी चुनौतियों पर चरचा करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का समाधान भारतीय संस्कृति में निहित है। आज तुलसी, पीपल, बरगद के पेड़ों को लगाने की जरूरत है। ताकि अनवरत ऑक्सीजन मिल सके। प्राचार्य डा. प्रभाष्कर राय ने राज्यमंत्री डॉ. अरुण सक्सेना का स्वागत किया। संचालन डॉ. सनिल वर्मा ने किया। एसडीएम जसराना नवनीत गोयल, सीओ जसराना शैलेंद्र कुमार शर्मा, सचिव मनोज प्रताप सिंह, कवि यशपाल, इंटर कालेज के प्रधानाचार्य श्यामपाल, तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह, जसराना चेयरमैन अवनीश गुप्ता, सिरसागंज चेयरमैन सोनी शिवहरे, मीडिया प्रभारी दीपक बघेल, भाजपा जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह राजपूत, राघवेंद्र सिंह मौजूद रहे।

योग दिवस पर बीएसएसएस के छात्रों ने मनाली खीरगंगा में किया योगाभ्यास

भोपाल समुद्र तल से 9,700 फीट की ऊँचाई पर हिमाचल प्रदेश की खीरगंगा यात्रा के दौरान भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के एडवेंचर सेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पर्वत की वादियों में योगाभ्यास किया। एडवेंचर सेल प्रभारी लेफ्टिनेंट नासिर अली के नेतृत्व में 92 छात्रों ने पर्वतों के बीच सामूहिक योग कर अन्य युवाओं को प्रतिदिन योग करने का संदेश भी दिया। मनाली-कसोल-खीरगंगा ट्रेकिंग ट्रिप के दौरान बीएसएसएस के छात्रों ने न केवल ट्रेकिंग का लुफ्त उठाया, बल्कि फिटनेस को भी प्राथमिकता में रखा। लेफ्टिनेंट नासिर अली ने बताया कि कॉलेज के लिये यह साल काफी खास रहा है। जहाँ एक ओर पूरा देश आजादी के 75 वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहा है, वही बीएसएसएस अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है। कॉलेज में विद्यार्थियों के लिये फिटनेस को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। इसी क्रम में इस वर्ष विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश की वादियों में एडवेंचर टूर करवाया गया है, जहाँ सभी ने उत्साह के साथ योग की विभिन्न प्रक्रियाएँ की।

आपदा में अवसर-कोसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों में ऐसे बढ़ रही है आमदनी

सुपौल बिहार के सुपौल जिला का लक्ष्मीनिया पंचायत में मखाने का खेती। फोटो- राहुल कुमार गौरवबिहार के सुपौल जिला का लक्ष्मीनिया पंचायत में मखाने का खेती। फोटो- राहुल कुमार गौरव बिहार के सुपौल जिला का लक्ष्मीनिया पंचायत में मखाने का खेती।मेरे पास एक ही जगह 3 बीघा खेत की जमीन है। जो रोड से 8-10 मीटर ज्यादा गहराई पर है।

2021 से पहले धान के सीजन में धान और गेहूं के सीजन में गेहूं और मूंग की खेती करता था, लेकिन बारिश होते ही सब बर्बाद हो जाता था। फिर गांव के ही किसान सलाहकार बेचन मंडल ने मखाना की खेती पर मिल रहे अनुदान के बारे में बताया। मुझे यह बात समझ में आ गई और अपने खेत के अलावा बगल वाले 4 बीघा खेत को 7200 रुपए प्रति बीघा की दर से बटिया पर ले लिया। पिछले साल मार्च महीने से मखाने की खेती शुरू कर दी। 2021 में 8 बीघा खेत से लगभग 3 लाख रुपए की शुद्ध आय हुई। अभी अनुदान के लिए आवेदन किया है, अनुदान मिलने से आमदनी और बढ़ जाएगी।÷ बिहार के सुपौल जिला के बभनी गांव के पंकज मिश्रा बताते है। बभनी गांव कोसी से सटा हुआ है, जहां अकसर बाढ़ के कारण लोगों को खेती का नुकसान हो जाता है। लेकिन अब यही बाढ़ का पानी उनके लिए आमदनी का जरिया बन गया है। पंकज की तरह कई किसान कोसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों में मखाने की खेती पर ध्यान दे रहे हैं।

ऐसे ही कोसी से सटे सहरसा जिले में मखाने की खेती का रकबा बढ़ रहा है। यहां के जिला उद्यान विभाग में कार्यरत संजीव कुमार झा बताते हैं कि इस वर्ष जिले में 90 हेक्टेयर से भी अधिक में मखाना की खेती हो रही है। वहीं पहले 30-35 हेक्टेयर में मखाना की खेती होती थी। संजीव बताते हैं कि कोसी नदी के आसपास का क्षेत्र मखाना के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यही वजह है कि सरकार ने मखाना विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के जरिए एक जिला एक उत्पाद के तहत सहरसा को मखाना के लिए चयनित किया गया है। किसानों को इसका फायदा भी मिल रहा है।सहरसा के बनगांव गांव के भरत खां इस बार 23 कट्ठे खेत में मखाने की खेती कर रहे हैं। भरत खां बताते हैं कि, ÷एक हेक्टेयर मखाने की खेती करने में कम से कम एक से डेढ़ लाख रुपया खर्च होता है। इतना रुपया गरीब किसान कहां से ला पाएगा। इसलिए पहले सिर्फ बड़े किसान मखाना की खेती करते थे। तालाब के अलावा कम से कम डेढ़ से दो फुट पानी वाले खेत में भी मखाने की खेती हो सकती है। छोटे किसान तालाब के बजाय खेत को खोदकर मखाने की खेती कर रहे हैं।÷ सुपौल जिले के लक्ष्मीनिया गांव भी चारों ओर कोसी नदी से घिरा हुआ है। हर साल नदी के बाढ़ का पानी इस गांव के खेतों तक पहुंच जाता है। इसलिए किसानों ने गेहूं धान छोड़ कर इस बार मखाने के साथ-साथ मछली पालन शुरू कर दिया है। गांव के मुखिया रोशन झा बताते हैं कि कोसी क्षेत्र के विभिन्न गांवों के दर्जनों किसान मखाना की

खेती कर अपनी तस्वीर बदल रहे हैं। बीना बभनगामा गांव के सुंदरपुर टोला के संजित मंडल तालाब पद्धति से मखाना व मछली पालन एक साथ कर रहे हैं। सहरसा जिले के किसान सलाहकार संघ के उपाध्यक्ष कुमार गणेश बताते हैं कि मछली पालन को लेकर सरकार की सब्सिडी योजना का फायदा किसानों को मिल रहा है। मछली पालन के लिए नए तालाब के निर्माण में 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दिया जा रहा है। मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदने पर भी सब्सिडी का प्रावधान है। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के प्रिंसिपल डॉ परसनाथ कहते हैं कि कोसी हमारे लिए वरदान है। कोसी की वजह से 10 से 15 फीट पर पानी मिल जाता है। इसी वजह से यहां मक्का और मखाने की खेती होती है। सिर्फ पूर्णिया जिले में 6,000 हेक्टेयर में मखाना की खेती होती है और उत्पादन 5280 टन। वहीं कटिहार जिले में 5000 हेक्टेयर में मखाना और 70,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है?। पूर्णिया अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले से लगभग 20 लाख टन मक्का दूसरे प्रांतों या विदेश में भेजे जाते हैं।

साभार - डाउन टू अर्थ

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008